देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

वॉल्यूम न.– 2022/palm/03 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | Saturday, February 12, 2022

क्या है शराब कंपनियों की गणित???

राजस्थान मे भी कंपनियो की गुटबाजी आई सामने!!!

PRICE-FIXING

Breweries, excise dept in a bind over pricing

Nirmal Tiwari

Jaipur: Liquor manufacturers are being accused of fixing the tax value due to the negligence of the Excise Department. After the Competition Commission of India (CCI) imposed a fine of Rs 870 crore in September last year on three beer makers and their trade association All India Brewers Association in the matter of brand and rate approval. Questions have been raised about the mess in brand and rate approval. The Excise Department has also come under the scanner due to the high increase in the rates of some brands of liquor in the last two years even as there is no significant increase in liquor production.

RTI activist Gyanesh Kumar alleges that in the last two years, the rates of some brands of liquor were increased excessively to benefit the liquor production and supply companies in the State, while their cost of production did not make much difference. In such a situation, crores of rupees were unnecessarily collected from the common consumer. Gyanesh Kumar has demanded a high level enquiry in this matter.

"The brand and rates of liquor are approved by the officers of RSBCL and Excise Department. In spite of not increasing the cost of production, there is something wrong with the excessive brands and the steep increase in their rates, there should be a fair investigation," said Former Deputy Commissioner of Excise Department Niranjan Sharma.

LIQUOR PRICES HIKED BY 50%

The rates of some brands of liquor were increased by 50% in two years. In the year 2018-19, about 683 brands and their rates were approved. RTI activist Gyanesh Kumar said that this fine was imposed on Submiler India, United Breweries and Carlsberg India. The CCI had also raided two liquor companies including Associate Alcohol & Breweries and Som Distilleries in October last year.

विशेष रिपोर्ट-3

कौन कौन है इस खेल मे शामिल?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

राजस्थान मे भी कंपनियो की गुटबाजी आई सामने!!!

जैसा कि इस प्रकरण के पहले अंक मे खुलासा किया था कि कैसे कुछ कंपनियाँ विशेष आपसी गुटबाजी कर, अपनी शराब/बीयर के ब्रांडो की दरे कम ज्यादा करने के खेल मे लिप्त है,और इस खेल का खुलासा सीसीआई द्वारा लिप्त कंपनियों पर भारी जुर्माना लगा कर किया गया है|इसी के साथ हमने इस बात का भी खुलासा किया था कि ऐसा ही खेल राजस्थान मे भी कुछ शराब कंपनियों और आबकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से कई वर्षो से खेला जा रहा है|यदि हम आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 और वर्ष 2021-22 हेतु जारी शराब के ब्रांडो की अनुमोदित रेट लिस्ट का गहराई से अध्ययन करे तो हमे पूरा खेल समझ मे आ सकता है|वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2021-22 मे अधिकतर बिकने वाले मुख्यता दो श्रेणियों की रेटो मे 200 से लेकर 300 रुपयों तक का इजाफा किया गया है यह श्रेणियाँ निम्न है:-

क्रम	नाम	2021-22	2018-19	रेटो मे अंतर
1	8 Pm Premium Black Exquisite Whisky	720		
2	Ac Black Luxury Pure Grain Whisky	720	515	205
3	Ac Black Pure Grain Whisky	720		
4	All Seasons Golden Collection Reserve Whisky	720	515	205
5	Dally Special Crafted Malt Whisky	735		
6	Magic Black Reserve Whisky	700		
7	Red Knight Finest Malt Blended Whisky	720	509	211
8	Reserve7 Rare Whisky	730		
9	Royal Challenge Premium Deluxe Whisky	720	523	197
10	Royal Green Classic Blended Whisky	720	514	206
11	Royal Stag Delux Whisky	720	515	205
12	Solan Number One Black Rare And Premium Whisky	720	515	205
13	Sterling Reserve B7 Deluxe Blended Whisky	720		
14	The Hawkston Nobel Reserve Superior Quality Whisky	730	528	202
15	Whiskin Craft Special Reserve Grain Whisky	720		

क्रम	नाम	2021-22	2018-19	रेटो मे अंतर
1	Antiquity Blue Ultra Platinum Whisky	1080	786	294
2	Ashwa Premium Malty Whisky	1075		
3	Back Bencher Whisky	1045		
4	Blenders Pride Select Premium Whisky	1035	740	295
5	Golfers Shot Barrel Aged Whisky	1035	741	294
6	Peter Scot Malt Whisky	1050	751	299
7	Rock Whisky	1035		
8	Rockford Classic Finest Blended Whisky	1075	782	293
9	Royal Pride Reserve Smooth Whisky	1035		
10	Royal Pride Reserve Whisky	1035		
11	Signature Premier Grain Whisky.	1070	768	302
12	Signature Rare Aged Whisky	1035	740	295
13	Star Walker Ultra Premium Blended Whisky Old Cask Collection	1035		
14	Sterling Reserve B10 Exclusive Blended Whisky	1035		
15	The Generation Premium Blended Whisky	1035	742	293

उपरोक्त आंकड़ो से स्पष्ट है कि विगत 4 सालो मे जो ब्रांड 500 से 550 की केटेगीरी के थे, उनकी दर तकरीबन 200 रुपए बढ़ा कर वर्तमान मे 700 से 750 के मध्य कर दी गयी गयी है|इसी प्रकार जो ब्रांड 700-800 के मध्य थे उनकी दर तकरीबन 300 रुपए बढ़ा कर 1000 से 1100 के मध्य कर दी गयी है|राजस्थान मे मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं मे अधिकतम शराब की बिक्री इन्ही दो श्रेणियों मे अधिक होती है|इस प्रकार विगत 4 सालों मे सरकार द्वारा इन ब्रांडो पर रेट बढ़ाकर, मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं पर अधिकतम बोझ डाला गया है|

जवाब मांगते सवाल?

1. राजस्थान सरकार द्वारा विगत 10 सालो मे कितनी शराब/बीयर कंपनियों के विभिन्न ब्रांडो की कीमते बढ़ायी गयी है?
2. राजस्थान सरकार द्वारा विगत 10 सालो मे कितनी शराब/बीयर कंपनियों के विभिन्न ब्रांडो की कीमते कम की गयी है?
3. विगत 10 सालो मे विभिन्न शराब/बीयर कंपनियों द्वारा कौन कौन से नए ब्रांड राज्य सरकार से पास करवाए गए,क्या सरकार द्वारा नए ब्रांडो की क्वालिटी और विशेषताओं की जांच करवायी गयी थी?नए ब्रांड और इनसे कमतर ब्रांडो के क्या क्वालिटी का फर्क था?इन ब्रांडो का उत्पादन और पेकेजिंग किन किन कंपनियों द्वारा की गयी?
4. शराब/बीयर कंपनियों द्वारा अपने ब्रांडो की कीमते बढ़ाने और कम करने मे क्या बड़ा खेल खेला जाता है?
5. इस खेल मे वित्त/आबकारी विभाग के कौन कौन अधिकारी शामिल है?
6. क्या विगत सालो मे CCI द्वारा शराब/बीयर कंपनियों की गुटबंदी के मामलो की वित्त/आबकारी विभाग द्वारा जांच करवाई गयी?
7. गुटबंदी के अलावा और किस प्रकार शराब/बीयर कंपनियों द्वारा स्वस्थ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को नुक्सान पहुंचाया जाता है?
8. विगत 10 सालो मे ऐसे कितने मामले राज्य सरकार/वित्त विभाग/आबकारी विभाग के संज्ञान मे आए?उन पर राज्य सरकार/वित्त विभाग/आबकारी विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?